फार्मा निर्यात को मदद देगी सरकार

हैदराबाद/ नई दिल्ली, 05 अप्रैल. देश के औषधि क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत भारत की फार्मा राजधानी के रूप में विख्यात हैदराबाद में शनिवार को आयोजित एक चिंतन शिविर में केंद्रीय वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने औषधि निर्यात क्षेत्र को सरकार की ओर से पूरे सहयोग का भरोसा दिलाया.

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की एक विज्ञप्ति के दुनिया के एक प्रमुख जैव प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में विख्यात हैदराबाद में इस कार्यक्रम का आयोजन केंद्र सरकार के वाणिज्य विभाग द्वारा फार्मास्युटिकल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया (फार्मेक्सिल) के सहयोग से किया गया. उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने की और कार्यक्रम में फार्माएक्सिल के पदाधिकारियों और आमंत्रित सदस्यों के अलावा वाणिज्य और औषधि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया. वाणिज्य सचिव ने गुणवत्तापूर्ण और किफायती दवाइयों के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की रणनीतिक पुनर्स्थापन की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि स्वास्थ्य सेवा में गुणवत्ता ही निर्णायक कारक बनी रहेगी. सचिव ने मूल्य, गुणवत्ता और लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने के लिए उद्योग के साथ मिलकर काम करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया और सत्र के दौरान निर्यातकों के साथ बातचीत करते हुए उनकी शंकाओं और चिंताओं का समाधान किया.

चर्चा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 79वें स्वतंत्रता दिवस संबोधन में स्वास्थ्य सेवा में नवाचार और आत्मनिर्भरता की आवश्यकता पर दिये गये बल का उल्लेख किया गया. प्रधानमंत्री ने कहा था- शोधकर्ताओं और उद्यमियों को नई दवाओं और चिकित्सा प्रौद्योगिकियों के लिए पेटेंट प्राप्त करना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि भारत न केवल अपनी स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करे, बल्कि चिकित्सा आत्मनिर्भरता और नवाचार का वैश्विक केंद्र भी बने, जिससे विज्ञान, प्रौद्योगिकी और मानव कल्याण में देश की नेतृत्व क्षमता प्रदर्शित हो.

> वाणिज्य सचिव श्री अग्रवाल ने भारत के औषधि उद्योग की मजबूत विकास गति पर प्रकाश डाला और कहा कि विश्व की लगभग 18-19 प्रतिशत आबादी वाला भारत स्वयं एक विशाल और विस्तारित बाजार है, जहां बढ़ती आय स्वास्थ्य सेवाओं की मांग को और बढ़ाएगी. वर्तमान में लगभग 60 अरब अमेरिकी डॉलर के मूल्य वाले इस उद्योग में निर्यात का लगभग 50 प्रतिशत योगदान है और यह अपने विशाल आकार, लागत प्रतिस्पर्धात्मकता और जेनेरिक दवाओं में वैश्विक नेतृत्व के कारण विश्व की फार्मेसी के रूप में उभरा है.

अमूल ने पार किया 1 लाख करोड़ टर्नओवर का आंकड़ा

नई दिल्ली, 05 अप्रैल. भारत की डेयरी इंडस्ट्री में एक नया इतिहास रचते हुए अमूल ने वित्त वर्ष 2026 में 1 लाख करोड़ (1 ट्रिलियन) का टर्नओवर पार कर लिया है. यह उपलब्धि न केवल कंपनी की मजबूत ग्रोथ को दर्शाती है, बल्कि यह भी साबित करती है कि भारतीय कोऑपरेटिव मॉडल अब वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना रहा है. लगभग 11प्रतिशत की सालाना वृद्धि के साथ अमूल ने घरेलू बाजार में अपनी पकड़ और मजबूत की है, वहीं यूरोप और अमेरिका जैसे बड़े अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कदम रखकर अपने विस्तार को नई दिशा दी है. गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के नेतृत्व में संचालित अमूल की सफलता के पीछे उसका व्यापक वितरण नेटवर्क, विविध उत्पाद पोर्टफोलियो और किसानों से जुड़ा मजबूत आधार है.

रेपो दरों में बदलाव की उम्मीद नहीं

भारतीय स्टेट बैंक की अनुसंधान इकाई एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट

नई दिल्ली, 05 अप्रैल. पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की सोमवार से शुरू हो रही तीन दिवसीय बैठक में रेपो दरों में बदलाव की उम्मीद नहीं है. भारतीय स्टेट बैंक की अनुसंधान इकाई एसबीआई रिसर्च की रविवार को जारी रिपोर्ट में यह बात कही गयी है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि एमपीसी की पिछली बैठक के बाद से पश्चिम एशिया संकट के रूप में दुनिया में एक बड़ा भू-राजनैतिक बदलाव आया है. विशेषकर हार्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने से वैश्विक व्यापार प्रभावित हुआ है. यह साल 1973 के बाद कच्चे तेल के बाजार में सबसे बड़ा व्यवधान है. रिपोर्ट के अनुसार, कच्चा तेल इस समय 100 डॉलर प्रति बैरल के पार है और रुपया 93 रुपये प्रति डॉलर से नीचे चल रहा है. साथ ही सुपर अल नीनो प्रभाव की भविष्वाणी की गयी है. इन सभी कारकों के मद्देनजर आरबीआई फिलहाल सावधानी बरतते हुए 08 अप्रैल को जारी होने वाले बयान में यथास्थिति बरकरार रखेगा. वित्त वर्ष 2025-26 में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारतीय पूंजी बाजार से 16.6 अरब डॉलर की शुद्ध निकासी की जो 1991 के बाद सबसे ज्यादा है.

> रुपया दबाव में है और 114 दिन में इसमें तीन रुपये प्रति डॉलर की गिरावट आ चुकी है. कच्चे तेल की कीमत ऊपर बनी हुई है. इन सबका सम्मिलित परिणाम यह होगा कि अगली तीन तिमाहियों में उपभोक्ता मूल्य आधारित मुद्रास्फीति की दर 4.5 प्रतिशत से अधिक रहेगी. मौसम वैज्ञानिकों ने इस साल जून और अगस्त के बीच अल नीनो प्रभाव के सक्रिय रहने की 62 प्रतिशत संभावना जतायी है. साथ ही इस साल सुपर अल नीनो रहने की बात कही गयी है. इसका मतलब है कि तापमान दीर्घावधि औसत से दो डिग्री सेल्सियस से भी अधिक रहेगा. इससे भारत में मानसून प्रभावित होगा जिस पर आज भी ज्यादातर खरीफ की खेती निर्भर करती है.

एफपीआई ने भारतीय पूंजी बाजार से निकाले 21,964 करोड़ रुपए

मुंबई, 05 अप्रैल. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने अप्रैल महीने में अब तक दो कारोबारी दिवस में भारतीय पूंजी बाजार से 21,964 करोड़ रुपये की शुद्ध निकासी की है.

शुद्ध निकासी एफपीआई द्वारा बाजार में निवेश की गयी राशि और निकाली गयी राशि का अंतर है. केंद्रीय डिपॉजिटरी सेवा के आंकड़ों के अनुसार, एफपीआई ने दो दिन में शुद्ध रूप से 19,837 करोड़ रुपये की इक्विटी बेची. डेट में भी उन्होंने 2,296 करोड़ रुपये की बिकवाली की. हाइब्रिड उपकरणों और म्यूचुअल फंड में उनका निवेश सकारात्मक रहा. उन्होंने हाइब्रिड उपकरणों में 1.12 करोड़ रुपये और म्यूचुअल फंड में शुद्ध रूप से 168 करोड़ रुपये लगाये. इससे पहले, मार्च में एफपीआई ने भारतीय पूंजी बाजार से 1,26,991 करोड़ रुपये निकाले थे जो अब तक की सबसे बड़ी निकासी है. फरवरी में उनका निवेश 37,847 करोड़ रुपये सकारात्मक रहा था जबकि जनवरी में उन्होंने 29,071 करोड़ रुपये निकाले थे. इस प्रकार मौजूदा कैलेंडर वर्ष में एफपीआई भारतीय पूंजी बाजार से 1,40,179 करोड़ रुपये की शुद्ध निकासी कर चुके हैं.

लगातार चौथे साल महिंद्रा ईवी ने कायम रखा दबदबा

एमएलएमएमएल) ने वित्त वर्ष2025-26 में भी अपना मजबूत बाजार नेतृत्व बनाए रखा

अब तक कुल मिलाकर 6 अरब से अधिक ई-किलोमीटर की दूरी तय

मुंबई, 05 अप्रैल. भारत की अग्रणी इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक वाहन निर्माता कंपनी महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी लिमिटेड (एमएलएमएमएल) ने वित्त वर्ष2025-26में भी अपना मजबूत बाजार नेतृत्व बनाए रखा. कंपनी लगातारचौथे वित्त वर्षमें भारत की नंबर-1 इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक वाहन निर्माताबनी रही.

यह उपलब्धि उन हजारों चालकों और बेड़ा (फ्लीट) मालिकों के विश्वास का प्रमाण है, जिन्होंने अपने उद्यमिता के सफर के लिए एमएलएमएमएल को चुना है. कंपनी ने वित्त वर्ष 2025-26 मेंएक ही वित्त वर्ष में 1 लाख से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है. अब तक कुल मिलाकर एमएलएमएमएल 3.4 लाख से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री कर चुकी है. एमएलएमएमएल कीएल-5 श्रेणी में मजबूत उपस्थिति है, जहां कंपनी की 39.7 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी है.

वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी की प्रमुख उपलब्धियां

वित्त वर्ष 2025-26 में1 लाख से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन बिक्री, यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली वाणिज्यिक वाहन निर्माता कंपनी बनी. अब तक कुल मिलाकर 6 अरब से अधिक ई-किलोमीटरकी दूरी तय, जिससे लगभग240 किलो मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जनमें कमी आई और भारत के स्थिरता लक्ष्यों को समर्थन मिला. वित्त वर्ष 2025-26 में एमएलएमएमएल ने अपने उत्पाद पोर्टफोलियो का विस्तार करते हुए महिंद्रा लॉन्च किया.

> ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखकर विकसित किए गए इस वाहन मेंसेगमेंट-फर्स्ट सुविधाएं जैसे रिवर्स थ्रॉटल, एयरो डायनामिक डिजाइन और200 किलोमीटर की वास्तविक ड्राइविंग रेंजदी गई है. नवाचार, भरोसेमंद तकनीक और पर्यावरणीय स्थिरता पर लगातार ध्यान देने के कारण एमएल एमएमएल भारत मेंलास्ट-माइल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी परिवर्तन में अग्रणी भूमिका निभा रही है. सभी आंकड़े सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटो मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (एसआईएएम) के अनुसार हैं.

आरबीआई की नीति से शेयर बाजार को मिलेगी दिशा

मुंबई, 05 अप्रैल. बीते सप्ताह गिरावट के बाद आने वाले सप्ताह में वैश्विक कारकों के साथ रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति संबंधी बयान से शेयर बाजार को दिशा मिलेगी. निवेशकों की नजर फिलहाल मुख्य रूप से ईरान युद्ध और पश्चिम एशिया संकट पर बनी हुई है.

इसका फिलहाल कोई हल निकलता नहीं दिख रहा. इससे निवेश धारणा कमजोर बनी हुई है. इसके अलावा, रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की गत 28 फरवरी को पश्चिम एशिया संकट शुरू होने के बाद पहली बैठक 06 अप्रैल को शुरू हो रही है. बैठक के फैसलों का भी बाजार पर असर दिखेगा. पिछले सप्ताह 31 मार्च को महावीर जयंती और 03 अप्रैल को गुड फ्राइडे के अवकाश के कारण बाजार में तीन दिन ही कारोबार हुआ. इसमें सोमवार को प्रमुख सूचकांकों में बड़ी गिरावट रही जबकि बुधवार और गुरुवार को प्रमुख सूचकांक हरे निशान में बंद हुए. बीएसई का सेंसेक्स सप्ताह के दौरान कुल 263.67 अंक (0.36 प्रतिशत) टूटकर गुरुवार को 73,319.55 अंक पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 सूचकांक भी 106.50 अंक यानी 0.47 प्रतिशत की साप्ताहिक गिरावट के साथ 22,713.10 अंक पर रहा. मझौली कंपनियों का निफ्टी मिडकैप-50 सूचकांक 0.82 प्रतिशत टूट गया.

जबकि स्मॉलकैप-100 सूचकांक लगभग अपरिवर्तित रहा. बीते सप्ताह सेंसेक्स की 30 में से 17 कंपनियों के शेयर टूट गये.

सनफार्मा में सबसे अधिक 5.62 प्रतिशत की साप्ताहिक गिरावट रही. एनटीपीसी का शेयर 4.23 प्रतिशत, अल्ट्राटेक सीमेंट का 3.85, बजाज फिनसर्व का 3.18, भारती एयरटेल का 2.86, बजाज फाइनेंस का 2.13 और कोटक महिंद्रा बैंक का 2.13 प्रतिशत नीचे बंद हुआ.. पावरग्रिड का शेयर 1.88 प्रतिशत, एशियन पेंट्स का 1.72 और आईसीआईसीआई बैंक का 1.47 प्रतिशत टूट गया. महिंद्रा एंड महिंद्रा, एचडीएफसी बैंक, आईटीसी, इटरनल, एक्सिस बैंक और हिंदुस्तान यूनीलिवर के शेयर लाल निशान में रहे.

> ट्रेंट में सबसे अधिक 4.52 प्रतिशत की साप्ताहिक बढ़त दर्ज की गयी. बीईएल का शेयर 4.14 प्रतिशत, टेक महिंद्रा का 3.63, अडानी पोर्ट्स का 2.97, टाइटन का 2.92, एचसीएल टेक्नोलॉजीज का 2.80 और टीसीएस का 2.59 प्रतिशत ऊपर रहा. इंफोसिस का शेयर 2.40 प्रतिशत, इंडिगो का 2.30, मारुति सुजुकी का 1.97 और एलएंडटी का 1.34 प्रतिशत चढ़ा. टाटा स्टील में भी तेजी रही.

सीआईआई ने निर्यातकों के लिए की प्रोत्साहन की मांग

नयी दिल्ली, 05 अप्रैल. भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने पश्चिम एशिया संकट के बीच केंद्र सरकार से सूक्ष्म, मझौले तथा लघु उद्यम (एमएसएमई) और निर्यातकों के लिए प्रोत्साहन की मांग की है.

संगठन ने मौजूदा समय में सरकार और रिजर्व बैंक द्वारा उठाए गए समयबद्ध, संतुलित और समन्वित कदमों की सराहना करते हुए रविवार को एक 20 सूत्री एजेंडा जारी किया. इसमें एमएसएमई के लिए आसान और सस्ती पूंजी उपलब्ध कराने, निर्यातकों के लिए ऋण और बीमा को मजबूत बनाने तथा ऊर्जा स्रोतों पर कर कम करने जैसे सुझाव दिये गये हैं. सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने कहा कि सरकार और रिजर्व बैंक के शुरुआती उपायों ने बाजार की भावना को स्थिर करने में मदद की है और यह दिखाया है कि देश का नीतिगत ढांचा बाहरी झटकों के सामने भी मजबूत और सक्षम है. उन्होंने कहा कि भारत के पिछले अनुभव बताते हैं कि समन्वित राजकोषीय और मौद्रिक कदम लचीलापन बढ़ाने में मदद करते हैं. अगला चरण लक्षित तरलता समर्थन, ऋण सुविधा, व्यापार लागत प्रबंधन और विदेशी मुद्रा स्थिरता पर केंद्रित होना चाहिये.

> सीआईआई की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स और व्यापार चैनलों में आपूर्ति पक्ष से संबंधित दबाव बने हुए हैं. उद्योग से प्राप्त फीडबैक के अनुसार, शुरुआती नीतिगत उपायों ने तत्काल प्रभाव को कम किया है, लेकिन कई क्षेत्रों - विशेषकर एमएसएमई, निर्यातक और ऊर्जा-गहन उद्योग - अब भी परिचालन और वित्तीय दबाव का सामना कर रहे हैं. सीआईआई ने अपने एजेंडा में आपात स्थिति के लिए क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम की मांग की है.

गोल्ड-सिल्वर में भारी गिरावट, निवेशकों को झटका

नई दिल्ली, 05 अप्रैल. पिछले एक महीने में सोने और चांदी की कीमतों में आई तेज गिरावट ने निवेशकों को बड़ा झटका दिया है. जहां एक ओर सोना 26,000 से ज्यादा सस्ता हो गया है, वहीं चांदी के दामों में 36,000 से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है. वैश्विक बाजार में बढ़ती अस्थिरता, युद्ध की स्थिति और डॉलर की मजबूती ने कीमती धातुओं पर दबाव बनाया है. 5 मार्च 2026 को जहां सोना 1,60,586 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था, वह 2 अप्रैल तक गिरकर 1,46,608 पर आ गया.

चावल, गेहूं में साप्ताहिक गिरावट

चीनी-खाद्य तेल मजबूत, दालों में घट-बढ़

नयी दिल्ली, 05 अप्रैल. घरेलू थोक जिंस बाजारों में बीते सप्ताह चावल के औसत भाव गिर गये. गेहूं में भी नरमी रही. चीनी और खाद्य तेलों के भाव बढ़ गये जबकि दालों में उतार-चढ़ाव देखा गया.

सप्ताह के दौरान चावल की औसत कीमत 27 रुपये टूटकर सप्ताहांत पर 3,825 रुपये प्रति क्विंटल रह गयी. गेहूं 15 रुपये गिरकर 2,784 रुपये प्रति क्विंटल बोला गया. आटा 17 रुपये सस्ता हुआ और 3,279 रुपये प्रति क्विंटल पर रहा. सप्ताह के दौरान तुअर दाल की औसत कीमत 76 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ गयी. मूंग दाल भी चार रुपये प्रति क्विंटल महंगी हुई. मसूर दाल में 40 रुपये और चना दाल में 27 रुपये की नरमी रही. उड़द दाल का भाव 11 रुपये प्रति क्विंटल टूट गया. बीते सप्ताह सोया तेल 223 रुपये प्रति क्विंटल महंगा हुआ. सरसों तेल की कीमत 194 रुपये बढ़ गयी. सूरजमुखी तेल का भाव 137 रुपये और मूंगफली तेल का 126 रुपये चढ़ा.

समाचार विशेष

सूची में के. अन्नामलाई का नाम क्यों नहीं?

चेन्नई. भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार दोपहर तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए 27 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी. इस लिस्ट की सबसे बड़ी चर्चा पार्टी के प्रमुख चेहरे के. अन्नामलाई का नाम न होने को लेकर रही, जिसने सभी को चौंका दिया.

बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री एल. मुरगन को अविनाशी सीट से मैदान में उतारा है, जबकि पूर्व राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन को चेन्नई की मायलापुर सीट से उम्मीदवार बनाया गया है, जो बीजेपी को मिली इकलौती सीट है. इसके अलावा तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष नैनार नागेंथ्रान को सत्तूर से टिकट दिया गया है. वहीं, भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वनाथी को श्रीनिवासन कोयंबटूर को कोयंबटूर (उत्तर) सीट से उम्मीदवार बनाया गया है. अन्य प्रमुख उम्मीदवारों में मोदक्कुरिची से कीर्तिका शिवकुमार (पूर्व कांग्रेस विधायक), विलावनकोड से एस. विजयधरानी और थल्ली से नागेश कुमार को मैदान में उतारा गया है.

एक मीडिया रिपोर्ट एक वरिष्ठ नेता के हवाले से यह दावा कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने के. अन्नामलाई के साथ कई दौर की बातचीत की थी और शीर्ष नेतृत्व चाहता था कि वह चुनाव मैदान में उतरें. हालांकि इसी रिपोर्ट में यह अन्नामलाई के करीबी सूत्रों के हवाले से यह बताया गया है कि उनका फैसला एनडीए में शामिल दलों के बीच अंतिम सीट बंटवारे पर निर्भर रहा. मामले की जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि अगर कोयंबटूर क्षेत्र में बीजेपी को एक अतिरिक्त सीट मिल जाती, तो अन्नामलाई चुनाव लड़ने पर जरूर विचार करते. तमिलनाडु चुनाव में एनडीए के सीट बंटवारे की चर्चा काफी दिनों से थी.

सीट बंटवारे में दिखा बीजेपी का बढ़ता प्रभाव

तमिलनाडु में सीटों का मौजूदा बंटवारा बीजेपी के सीमित लेकिन लगातार बढ़ते राजनीतिक प्रभाव को दर्शाता है. साल 2021 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 20 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से उसे 4 सीटों पर जीत मिली थी. इस बार बीजेपी को 27 सीटें मिली हैं जो उसके विस्तार की ओर इशारा करती हैं. कई जानकारों का मानना है कि इस बार सिर्फ सीटों की संख्या ही अहम नहीं है बल्कि राज्य के अलग-अलग क्षेत्रों में फैली सीटें ज्यादा महत्वपूर्ण हैं. यही फैक्टर भाजपा के अंदर जीत की उम्मीदों को मजबूती दे रहा है.

बंगाल चुनाव में पहाड़ों का 'पंचकोणीय' खेल

क्या अजय एडवर्ड्स बिगाड़ देंगे दिग्गजों का सियासी गणित?

कोलकाता. पश्चिम बंगाल की राजनीति जब मैदानों से निकलकर पहाड़ों की घुमावदार वादियों में पहुंचती है, तो वहां की फिजां और चुनावी समीकरण दोनों पूरी तरह बदल जाते हैं. आगामी दिनों होने वाले विधानभा चुनावों के लिए राज्य की 294 सीटों पर बिसात बिछ चुकी है.

दिलचस्प बात यह है कि जहां राज्य की अधिकांश सीटों पर चार प्रमुख ताकतों के बीच मुकाबला सिमटा हुआ है, वहीं दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और कुर्सियांग जैसी 'पहाड़ों की रानी' कही जाने वाली सीटों पर इस बार 'पंचकोणीय' संघर्ष देखने को मिल रहा है. यह केवल पांच उम्मीदवारों की लड़ाई नहीं है, बल्कि पहाड़ों के भविष्य और पहचान की एक नई जंग है, जिसे हर दल अपने-अपने चश्मे से देख रहा है. मैदान की राजनीति से अलग पहाड़ों में इस बार नए समीकरण बन रहे हैं. पश्चिम बंगाल की अधिकांश सीटों पर मुकाबला तृणमूल कांग्रेस, भाजपा, वाम मोर्चा-एआईएसएफ गठबंधन और कांग्रेस के बीच सिमटा हुआ है. लेकिन दार्जिलिंग की पहाड़ियों में प्रवेश करते ही यह चुनावी तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है. यहां की तीन महत्वपूर्ण सीटों- कुर्सियांग, कलिम्पोंग और दार्जिलिंग पर चुनावी लड़ाई अब पंचकोणीय हो चुकी है. इन क्षेत्रों में भाजपा को बिमल गुरुंग के गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का साथ मिला है, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने अनित थापा के भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा (बीजीपीएम) पर भरोसा जताया

> **एडवर्ड्स की एंट्री ने उड़ाई सूरमाओं की नींद**
>
> इस बार के पहाड़ी चुनाव में सबसे बड़ा 'एक्स-फैक्टर' बनकर उभरे हैं अजय एडवर्ड्स और उनकी पार्टी भारतीय गोरखा जनशक्ति मोर्चा. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आईजीजेएफ का स्वतंत्र रूप से चुनावी मैदान में उतरना जीजेएम समर्थित भाजपा और बीजीपीएम समर्थित तृणमूल कांग्रेस, दोनों के लिए बड़ी चुनौती बन गया है. इन क्षेत्रों में गोरखा मतदाता ही जीत और हार का फैसला करते हैं.

घरेलू सहायिका से चुनावी मैदान में कलिता

कोलकाता. बंगाल विधानसभा चुनाव में पूर्व बर्द्धमान जिले की आउसग्राम सीट पर इस बार चुनावी मुकाबला सिर्फ दलों का नहीं, बल्कि एक आम महिला के संघर्ष और व्यवस्था के बीच सीधी टक्कर बन गया है.

भाजपा ने एक ऐसा चेहरा यहां से उतारा है, जिसने चुनावी बहस को नई दिशा दे दी है. घरों में काम करने वाली कलिता माजी यहां से भाजपा की उम्मीदवार बनकर मैदान में हैं. वह इलाके की बुनियादी समस्याओं को लेकर सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस को खुली चुनौती दे रही हैं. कलिता, जो अब तक दो घरों में काम कर महीने के महज चार हजार रुपये कमाती थीं, अब चुनावी मैदान में उतरकर राजनीति के केंद्र में हैं. बंगाल चुनाव के लिए भाजपा ने मंगलवार को उम्मीदवारों की अपनी चौथी सूची जारी कर दी, जिनमें सबसे प्रमुख नामों में केंद्रीय राज्यमंत्री शांतनु ठाकुर की पत्नी सोमा ठाकुर और हाल में कांग्रेस छोड़कर पार्टी में शामिल हुए कोलकाता नगर निगम में लगातार चार बार के पार्षद संतोष पाठक का है.

विशेष | क्या महिलाएं पलट देंगी चुनावी बाजी?

भाजपा को गढ़ बचाने की बड़ी चुनौती

पुडुचेरी. पुडुचेरी की राजनीति में मन्नाडिपेट विधानसभा क्षेत्र का अपना एक खास महत्व रहा है. 9 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए अब सियासी पारा चढ़ने लगा है. पुडुचेरी की 30 विधानसभा सीटों में से यह सीट सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित है और पांडिचेरी जिले का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है.

लगभग 39 वर्ग किलोमीटर में फैले इस क्षेत्र में मनालीपपेट, चेट्टीपेट और सुथुकेनी जैसे इलाके शामिल हैं. मन्नाडिपेट की

जनता हमेशा से लोकतंत्र के इस उत्सव में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेती आई है, जिसका अंदाजा यहां के पिछले मतदान प्रतिशत से लगाया जा सकता है.

इस निर्वाचन क्षेत्र का राजनीतिक इतिहास काफी दिलचस्प रहा है. साल 2021 के चुनावों में यहां एक बड़ा बदलाव देखने को मिला था, जब भारतीय जनता पार्टी के ए. नमशिवायम ने जीत का परचम लहराया था. उन्होंने डीएमके के ए. कृष्णन को 2,750 वोटों के अंतर से हराया था. उस समय भाजपा को यहां करीब 52.61 प्रतिशत वोट मिले थे. हालांकि, इससे पहले 2011 और 2016 के चुनावों में यहां एआईएनआरसी का दबदबा रहा था. यह देखना रोमांचक होगा कि क्या भाजपा अपनी पिछली जीत की लय को बरकरार रख पाती है या फिर क्षेत्रीय दल अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने में कामयाब होते हैं. मतदाताओं के मन में इस बार विकास और स्थानीय मुद्दों को लेकर कई सवाल हैं.

भाजपा के सामने पिछला प्रदर्शन दोहराने की चुनौती- सत्ताधारी दल के लिए मन्नाडिपेट की जंग इस बार आसान नहीं मानी जा रही है. 2021 में मिली जीत का अंतर लगभग 9.54 प्रतिशत था, जो पिछले चुनावों की तुलना में काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा है. 2016 में तो जीत का अंतर महज 419 वोट ही था. आंकड़ों के इस खेल के बीच, आम मतदाता अब केवल पार्टी का चेहरा नहीं, बल्कि काम की रिपोर्ट देख रहा है.

> **महिला शक्ति तय करेगी मन्नाडिपेट का भविष्य**
>
> मन्नाडिपेट के चुनावी आंकड़ों का सबसे दिलचस्प पहलू यहां की महिला मतदाता हैं. 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए तैयार की गई मतदाता सूची के अनुसार, यहां कुल 31,063 पंजीकृत मतदाता हैं. इनमें पुरुषों की संख्या 14,600 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 16,460 तक पहुंच गई है. यहां का लिंगानुपात 1127 है, जो स्पष्ट करता है कि जीत का रास्ता महिलाओं के समर्थन से ही होकर गुजरेगा. पिछले कई चुनावों से महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के मुकाबले ज्यादा प्रभावी रही है. ऐसे में राजनीतिक दलों के लिए महिला सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दे सबसे बड़े चुनावी हथियार बन गए हैं.